



## केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिये 735 पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी

### चर्चा में क्यों?

12 नवंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के वधिय और बुंदेलखंड जैसे- जल-दबाव वाले क्षेत्रों में पाइप से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिये 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी।

### प्रमुख बंदि

- जल शक्ति मिशन के क्रयान्वयन की गतिको तेज करने के लिये राज्यस्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन का प्रावधान करने के लिये राज्य द्वारा प्रस्तुत 1,882 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी।
- इन योजनाओं से 33 जिलों के 1,262 गाँवों की करीब 39 लाख की आबादी को कवर किया जाएगा। समतिद्वारा 735 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। मंजूरी के तहत प्रदेश के 4.03 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन दिये जाएंगे।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सहि शेखावत ने 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिये राज्य को पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया।
- अब तक राज्य के 2.64 करोड़ में से 34 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में नल का पानी मलि रहा है। 2021-22 में राज्य ने 78 लाख से अधिक घरों में नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है।
- राज्य सरकार अगले महीने से बुंदेलखंड और वधिय क्षेत्र के सैकड़ों गाँवों में हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराना शुरू करेगी। इसके लिये कई इलाकों में ट्रायल किये जा रहे हैं।
- जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिये की जाने वाली योजनाओं पर वचिर और अनुमोदन हेतु राज्यस्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) के गठन का प्रावधान है।
- SLSSC, भारत सरकार के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (NJJM) के नॉमिनी के साथ जल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं पर वचिर करने के लिये एक राज्यस्तरीय समति के रूप में कार्य करती है।